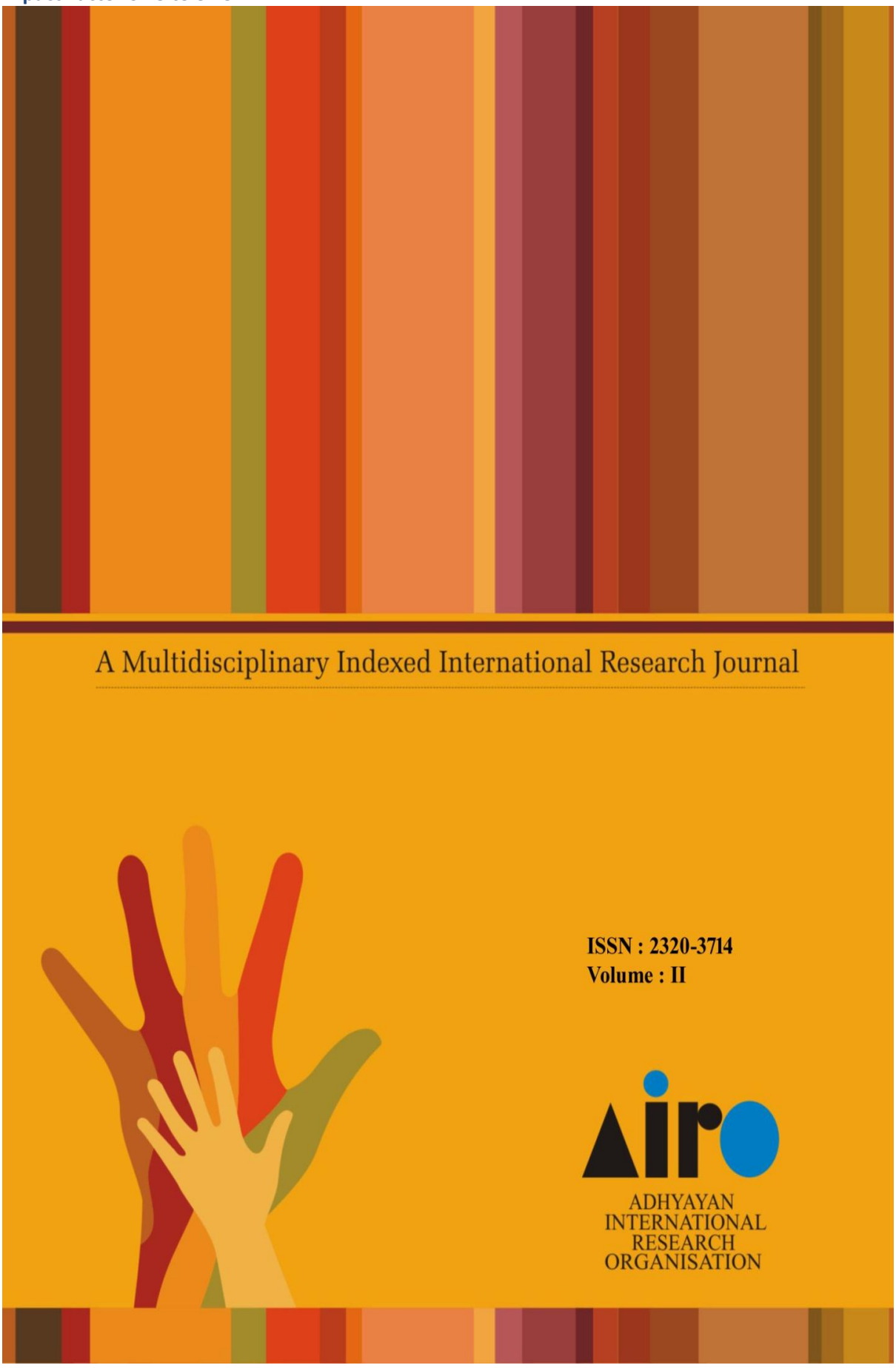
A Multidisciplinary Indexed International Research Journal
ISSN : 2320-3714
Volume : II
Airo
ADHYAYAN
INTERNATIONAL
RESEARCH
ORGANISATION

Airo International Research Journal July, 2013
Volume II, ISSN: 2320-3714
Impact Factor 0.75 to 3.19

भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सरकारी योजनाएँ

Dr. Krishna Kumar Thakur

Asst. Professor Hindi Century Cement College Baikunth (C.G.) Dist. Raipur

Declaration of Author: I hereby declare that the content of this research paper has been truly made by me including the title of the research paper/research article, and no serial sequence of any sentence has been copied through internet or any other source except references or some unavoidable essential or technical terms. In case of finding any patent or copy right content of any source or other author in my paper/article, I shall always be responsible for further clarification or any legal issues. For sole right content of different author or different source, which was unintentionally or intentionally used in this research paper shall immediately be removed from this journal and I shall be accountable for any further legal issues, and there will be no responsibility of Journal in any matter. If anyone has some issue related to the content of this research paper's copied or plagiarism content he/she may contact on my above mentioned email ID.

सारांश:- आज, सरकार और समाज के सामने यक्ष-प्रश्न है कि आखिर कब तक, मजबूर होकर, अन्नदाता किसान, सल्फास का जहर खाकर या फंदे से लटक कर, आत्महत्या करता रहेगा? खेती किसी भी मुल्क के जिंदा रहने की बुनियाद होती है। जब बुनियाद ही नहीं रहेगी, तो ढांचा बिखर जायेगा। हम चाहे जितनी तरक्की कर लें, लेकिन किसानों की तरक्की के बगैर सही मायने में देश खुशहाल नहीं होगा। आज, खेती मौत की फसल में बदल चुकी है। आंकड़े भयावह हैं। वर्ष *2013* में कुल *23,544* किसानों ने आत्महत्या की। यह घोर विडंबना है कि कृषि प्रधान भारत में, आर्थिक दिवालियेपन से पीड़ित, प्रति *22* मिनट में एक अन्नदाता किसान खुदकुशी कर रहा है। राष्टीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों के अनुसार सन् *1995-2010* के पंद्रह वर्षों में *2* लाख *56* हजार *949* किसानों ने आत्महत्या की।यह अध्ययन भारत में किसान आत्महत्याओं के कारणों की जांच करता है सही कीमत पाने में असमर्थता, फसल की विफलताएं, और दुर्गम ऋण ऐसे कारक हैं जो किसानों को इस चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस संबंध को समझना मांग प्रबंधन नीतियों (सरकार द्वारा पढ़ें, हस्तक्षेप और केंद्रीय बैंक) के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है।

मुख्य शब्द - आत्महत्या, विदर्भ, किसान, सरकारी योजनाए।

प्रस्तावना:-भारत देश की सबसे बड़ी इकाई गांव है। गांव में सामुदायिक भावना होती है। हमारा देश प्राचीनकाल से ही कृषि प्रधान देश है, उस समय लोगो का मुख्य पेशा पशुपालन व खेती उद्योग था। देश के किसान गरीब को पेट भरने के लिए अन्न, वस्त्र निवारा साहूकार और महाजनों ने छिना है। धूप तथा वर्षा से बचने के लिए उनके सिर पर छप्पर नहीं है। बंजर भूमि को समतल करके खेती योग्य बनाया। जहां सिचाई के लिए पानी एवं उपजाऊ भूमि थी। किसानों के लिए खेती 1965-66 में आई हरित क्रांति की दें है। जैविक खेती दूसरी हरित क्रांति भरपूर सिचाई पर आधारित है। फसल सूखने तथा कर्ज के तले दबने से किसान आत्महत्या कर रहा है। आज भारतीय किसान भयावह आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। किसान

विविध समस्याओं से ग्रस्त है। भारत में कृषि के पिछड़े होने की समस्या महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके पीछे प्राकृतिक कारण, जनसंख्या विस्फोट, परम्परागत अनुपयोगी कृषि तंत्र, आर्थिक साधनों की कमी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या, ग्रामीण बेरोजगारी, तथा प्राकृतिक प्रकोप, आधुनिक खेती तकनीकी ज्ञान का अभाव, सरकार की उदासीनता, सरकारी योजनाओं का सही तरह से क्रियान्वयन न होना इन कारणों से किसान आत्महत्या कर रहा है।

भारत में किसानों की आत्महत्याओं के बारे में लोकप्रिय प्रेस में रिपोर्टिंग 1990 के दशक के मध्य में शुरू हुई, विशेष रूप से पलामि साईंनाथ ने। 2000 के दशक में, इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और भारतीय सरकार की विविधताएं प्राप्त हुईं, भारत के गृह मंत्रालय सरकार के एक कार्यालय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, 1950 के दशक से भारत के आत्महत्या के आंकड़ों को इकट्ठा और प्रकाशित कर रहा है, जैसा कि वार्षिक आकस्मिक मृत्यु और भारत में आत्महत्या रिपोर्टें यह 1995 से किसान के आत्महत्या के आंकड़ों को अलग-अलग इकट्ठा और प्रकाशित करना शुरू कर दिया। वास्तविक एनएसीबी रिपोर्ट में प्रकाशित वास्तविक जनसांख्यिकीय विघटन शुरू हुआ, उस साल भारत में 134,599 आत्महत्याएं दर्ज की गईं, जो कि 12% से कम 15 9 64 खेती खेती के थे समुदाय, हालांकि किसान अरब-मजबूत भारतीय आबादी के लगभग दो-तिहाई हैं। तुलना में, 25,058 में गृहिणियां और 39,365 में गैर-खेती में स्व-रोजगार (व्यवसाय + पेशेवर + अन्य) अधिक आत्मघाती हैं। इसके अलावा, पूरी आबादी में आत्महत्या का प्रमुख कारण पारिवारिक समस्याएं और बीमार स्वास्थ्य, आर्थिक विफलता, दिवालिया होने आदि के साथ, लगभग 20% प्रत्येक, 6% पर आ रही हैं। वैश्विक डेटा बिंदु के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में आत्महत्या 314 मिलियन की आबादी के लिए लगभग 37,000 प्रतिवर्ष है।

भारत में, किसानों, सूखे, और ऋण, आनुवांशिक रूप से संशोधित बीज, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सरकारी आर्थिक नीतियों का उपयोग सहित, क्यों आत्मसमर्पण करने के लिए विभिन्न कारणों की पेशकश की गई है। मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, लेकिन अध्ययनों में आत्महत्या के शिकार लोगों को एक से अधिक कारणों से प्रेरित किया जाता है, आत्महत्या करने के लिए औसतन तीन या अधिक कारणों पर। पनगारीय कहता है कि, "आत्मसमूह के कारणों के कारण खेत से संबंधित कारणों का लगभग 25 प्रतिशत उल्लेख किया जाता है" और, "आत्महत्या करने वाले किसानों के बीच अध्ययन में लगातार अधिक कर्ज का बोझ और ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर अधिक निर्भरता दिखाई देती है"।

भारत में किसान की आत्महत्या के कारण निम्नानुसार हैं;

Reasons for farm suicides	Percent (of suicides)
Habits like drinking, gambling, etc.	20.35
Failure of crops	16.81
Other reasons (e.g. chit fund)	15.04
Family problems with spouse, others	13.27
Chronic illness	9.73
Marriage of daughters	5.31
Political affiliation	4.42
Property disputes	2.65
Debt burden	2.65
Price crash	2.65
Borrowing too much (e.g. for house construction)	2.65
Losses in non-farm activities	1.77
Failure of bore well	0.88

2014 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि उच्च जोखिम वाले किसानों से जुड़े तीन विशेष लक्षण हैं: "उन लोगों को जो कि कॉफ़ी और कपास के रूप में नकदी फसलों का उत्पादन करते हैं, जो कि एक हेक्टेयर से कम के" सीमांत "खेतों वाले हैं, और जो 300 रुपये या अधिक।" अध्ययन में यह भी पाया गया कि भारतीय राज्यों में जहां इन तीन विशेषताओं में सबसे ज्यादा आम हैं, उनमें उच्चतम आत्महत्या की दर है और " राज्य स्तर के आत्महत्याओं में लगभग 75% परिवर्तनशीलता के लिए जिम्मेदार है।" 2012 के एक अध्ययन ने किसानों पर एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण " ग्रामीण विदर्भ (महाराष्ट्र) में आत्महत्या करवाया और आत्महत्या करने के लिए किसी को खो दिया है, जो किसानों के परिवारों के बीच गुणात्मक व्यक्तित्व को गुणात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए स्मिथ की नम्रता पद्धति को लागू किया। किसान आत्महत्याओं के पीछे महत्व के कारण व्यक्त किए गए ऋण - शराब, शराब की लत, पर्यावरण, कम उत्पादन मूल्य, तनाव और परिवार की जिम्मेदारियां, उदासीनता, गरीब सिंचाई, खेती की बढ़ी हुई लागत, निजी धन उधारदाताओं, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग और फसल की विफलता का कारण दूसरे शब्दों

में तनाव को तनाव और परिवार की जिम्मेदारियों को उर्वरक और फसल की विफलता से काफी अधिक के रूप में मूल्यांकन किया गया। 2006 में एक ही क्षेत्र में एक अलग अध्ययन में, ऋणी (87%) और आर्थिक स्थिति में गिरावट (74%) आत्महत्या के लिए प्रमुख जोखिम कारक साबित हुई थी।

2004 से 2006 के अध्ययनों ने किसानों की आत्महत्या के लिए कई कारणों की पहचान की, जैसे अपर्याप्त या जोखिम भरा क्रेडिट सिस्टम, अर्द्ध शुष्क क्षेत्र खेती की कठिनाई, गरीब कृषि आय, वैकल्पिक आय के अवसरों की कमी, शहरी अर्थव्यवस्था में एक मंदी जो गैर-किसानों को मजबूर करती थी खेती में, और उचित परामर्श सेवाओं की अनुपस्थिति [2004 में, अखिल भारतीय बायोडायनायमिक और कार्बनिक फार्मिंग एसोसिएशन के अनुरोध के जवाब में, मुंबई उच्च न्यायालय ने टाटा इंस्टीट्यूट से महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याओं पर एक रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता की थी, और संस्थान ने मार्च 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सर्वेक्षण में कहा गया है कि "सरकारी उदासीनता, किसानों के लिए सुरक्षा निवारण की अनुपस्थिति, और कृषि से संबंधित जानकारी तक पहुंच की कमी राज्य के किसानों की हताश हालत के लिए मुख्य कारण है। 2002 में आयोजित पीड़ितों के बीच उद्यमों की गतिविधियों (जैसे कि नई फसलों, नकदी फसलों, और निम्नलिखित में प्रवेश करना) बाजार के रुझान) और सीमाओं की वजह से अपेक्षित लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी विफलता

साहित्य की समीक्षा:भारत सरकार में कृषि, किसानों और आत्महत्या से संबंधित जानकारी है। कृषि क्षेत्र में आँकड़ों तक सार्वजनिक पहुंच है, साथ ही साथ सभी सरकारी योजनाओं (कार्यक्रमों) का डेटाबेस तैयार किया गया है। कृषि आंकड़ों की आबादी, विकास, उत्पादन और कुछ फसल की पैदावार, गरीबी रेखा के नीचे आबादी का प्रतिशत और अन्य आंकड़ों के आंकड़े मौजूद हैं। योजनाओं के डेटाबेस में प्रायोजक, विवरण, लाभार्थियों, लाभ, और पात्रता आवश्यकताओं के बारे में जानकारी शामिल है।

कुछ साहित्य (मिश्रा, 2006, फर्नांडो एट अल, 2009, देशपांडे, 2010, ज्ञानमुद्र, 2007) सामाजिक, न्यूरोबोलॉजिकल और व्यक्तिगत समस्याओं की चर्चा करता है और अक्सर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि " अधिकांश आत्मघाती पीड़ितों को निदान योग्य मनोवैज्ञानिक बीमारी / विकार है" (मिश्रा , 2006) निराशा से पीड़ित लोगों के लिए या आत्महत्या पर विचार करने के लिए कई सार्वजनिक या स्थानीय सेवाएं नहीं हैं अक्सर यह सुझाव दिया जाता है कि आत्महत्या की रोकथाम की अधिक रणनीतियां लागू की जा रही हैं (इसलिए स्वास्थ्य समस्या के रूप में किसानों की आत्महत्या की ओर देखते हुए)

क्योंकि यह पाया गया कि शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में आत्महत्या की उच्च दर का हिस्सा भाग में था। मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं (ज्ञानमुद्र, 2007)।

किसान आत्महत्याएं भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में असमानता का एक अभिव्यक्ति है। किसान आत्महत्याओं से प्रभावित लोग गरीब और निचले जाति हैं आत्महत्या के मुख्य कारण अक्सर उद्धृत होते हैं ऋणी और फसल की विफलता (ज्ञानमुद्र, 2007)। अभी भी भारत में जाति व्यवस्था के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या है, जो अपने आप में एक और मुद्दा है, हालांकि किसान आत्महत्याएं इस समस्या के प्रतिनिधि हैं। अनिवार्य रूप से, निचली जातियों या निचले आय में रहने वाले लोगों को सरकार या मीडिया से मिलने वाली सहायता या योग्यता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए, निचली जातियों की कई समस्याओं को अनदेखी की जाती है।

मुजुमदार (2002)का प्रतिनिधित्व करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कृषि क्षेत्र के प्रवाह को रोकने के दिमाग के कारण कृषि क्षेत्र में 40 प्रतिशत प्राथमिकता सेक्टर ऋण लक्ष्य और 18 प्रतिशत ऋण का उप लक्ष्य निरंतर निरस्त किया है। 1 99 1 से पहले 1 99 1 से पहले 1 99 1 से पहले 41% से गिरावट आई है और 1 995-9 6 में लगभग 37% और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अग्रिम मार्च 1998 में कृषि क्षेत्र में 16% से अधिक नेट बैंक ऋण से कम थी। अध्ययन ने यह सुनिश्चित किया कि वार्षिक वृद्धि दर 1 9 70 से पहले क्रमशः कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में निश्चित निवेश और कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का निवेश क्रमश: 5 से 6 प्रतिशत और 7 प्रतिशत था, जो क्रमश: लगभग नकारात्मक और 3 प्रतिशत था। यह 1990 के दशक के दौरान निरंतर गिरावट आई थी और उतार-चढ़ाव का कोई हौसला नहीं था।

देशपांडे आर (2002)उत्तर कर्नाटक में किसानों के संकट के कारणों का तर्क देते हैं और किसानों की समस्याओं को हल करने के उपाय करते हैं। पिछले साठ वर्षों की योजना अवधि के दौरान कृषि नीति के लागू होने के कारण किसानों के संकट के कारण छिपे हुए हैं। नीति में कृषि के व्यावसायीकरण, मोनोकलल्चर के अनुकूलन और मिट्टी के अधिक शोषण, गैर-आर्थिक आधार पर फसल की खेती, प्रौद्योगिकी में बदलाव, वैश्विक परिवर्तनों के अपर्याप्त ज्ञान, पट्टे की व्यवस्था, अविनाशी वर्षा, घटिया गुणवत्ता की जानकारी, उच्च मूल्य विपणन ढांचे की अनुपस्थिति, भारी ऋण का बोझ, विस्तार सेवाओं की विफलता, कृषि उत्पाद की कीमतों में अस्थिरता, कीटों और रोगों का आकस्मिक हमलों और यह कर्नाटक राज्य के किसानों के बीच बढ़ती संकट की ओर अग्रसर है।

विद्यासागर और चंद्रा (2004)ने बताया कि कर्ज जाल, सूखा और फसल की विफलता के कारण करीब 3,000 आंध्रप्रदेश के किसानों ने

पांच साल में आत्महत्या कर ली। भारत में किसानों की आत्महत्याओं पर सरकार के नजरिए से विद्यासागर और चंद्रा द्वारा समीक्षकों का विश्लेषण किया गया है जो तर्क देते हैं कि किसानों की आत्महत्याओं को व्यक्तिगत समस्या में नहीं बदला जा सकता है, बल्कि वे कृषि संकट से संबंधित हैं। यह भी एक विचार था कि आत्महत्या करने वालों को पूर्व-अनुग्रह भुगतान आत्महत्याओं को प्रोत्साहित करेगा। उनके अध्ययन से पता चला कि ऋण जाल किसानों का मुख्य कारण आत्महत्या करने के चरम कदम उठा रहा था। कर्ज के जाल को एक तरफ कृषि संकट और अन्य पर संस्थागत ऋण की अनुपलब्धता के कारण कड़ा कर दिया गया। कोई संस्था कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि समुदाय को पैसा उधार नहीं दे रही थी जिसके लिए वे शहरी मध्यवर्गीय को पैसा उधार देते हैं। इस प्रकार, किसान गैर-संस्थागत ऋण पर निर्भर करते हैं कई मामलों में, गैर-संस्थागत स्रोतों (धन उधारदाताओं) से भारी दबाव और अपमान के कारण आत्महत्या के चरम कदम को सहारा के रूप में लिया गया था।

जयती घोष (2005)के मुताबिक, राज्यों में राज्यों ने सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से 1 9 0 के दशक के बाद नव-उदारवादी आर्थिक एजेंसियों को सक्रिय रूप से अपनाया है। आर्थिक सुधारों में कृषि के लिए किसी विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पैकेज शामिल नहीं थे। यह केवल औद्योगिक विकास पर केंद्रित है सरकारी खर्चे और वित्तीय उपायों के पैटर्न में बदलाव हैं, जो कि खेती की शर्तों को जरूरी प्रभावित करते हैं। वित्तीय और व्यापारिक विवाद के कारण खेती, ऋण, व्यापार और ग्रामीण आजीविका प्रभावित हुई। इस संकट अधिनियम का मुख्य कारण मुख्य रूप से सामान्य रूप से सार्वजनिक नीति से संबंधित है और विशेष रूप से पोस्ट सुधारों के बारे में। नई आर्थिक नीति ने व्यवस्थित रूप से किसानों को दी गई सुरक्षा को कम कर दिया और पर्याप्त नियमन के बिना बाजार अस्थिरता और निजी मुनाफाखोरी के लिए उन्हें उजागर किया। यह पद सुधारों की अवधि के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गिरावट का महत्वपूर्ण कारण रहा है। वित्तीय उदारीकरण के बाद केवल संस्थागत क्रेडिट आपूर्ति सूख गई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शहरी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण जमाओं को सुरक्षित और विशिष्ट उधार देने से अधिक लाभ बनाने के लिए स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। इसलिए, किसानों को अपनी क्रेडिट आवश्यकताओं के लिए निजी स्रोतों का सहारा लेना होगा। व्यापार उदारीकरण के बाद किसानों को उनके हाथ में न्यूनतम आय होती है जिसमें, न तो वे और न ही वे बनाए जाते हैं न ही वे ऋण राशि चुकौती कर सकते हैं कुल मिलाकर, कृषि संकट के कारण और 1 99 0 के दशक के दौरान पेश की गई उदार नीतियों से आत्मघाती व्यवहार उत्पन्न हुए हैं।

टीआईएसएएस (2005)टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, तुलजापुर (एमएच) ने 15 मार्च 2005 को मुंबई उच्च न्यायालय को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। टीआईएसएस की टीम ने अध्ययन के लिए विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश के 12 जिलों के 36 आत्मघाती शिकार किसानों का चयन किया है। किसानों की आत्महत्या का प्रमुख कारण ऋणी है। लगातार फसल की असफलता और उत्पादन के मूल्य से अधिक मूल्य की खेती लागत किसानों के बीच बढ़ती कर्जबाजारी के प्रमुख जिम्मेदार कारक हैं। इसलिए, किसानों ने बैंकों के कर्ज का भुगतान नहीं किया। लगभग 75 प्रतिशत किसानों ने गैर-संस्थागत एजेंसियों से ऋण लिया था और इसे चुकाने नहीं कर सका। इससे निराशा होती है और कुछ किसानों को आत्महत्या का निर्णय लिया जाता है। समिति ने तत्काल राहत, पुनर्वास और मुद्दे को हटाने के उपायों की सिफारिश की है।

सुचा एस। गिल (2005)ने आर्थिक कठिनाई, ऋणी और आत्महत्या के बीच घनिष्ठ संबंध का अध्ययन किया और स्थापित किया। इस अध्ययन में पाया गया कि गरीब आर्थिक स्थितियों ने ऋणग्रस्तता को जन्म दिया और कभी-कभी आर्थिक संकट से आत्महत्या का कारण बन गया। 59.9 प्रतिशत मामलों में, यह परिवार के सदस्यों के बीच एक झगड़ा था, मुख्य रूप से ऋणी या आर्थिक कठिनाई के कारण होता है ऋण की वापसी और सामाजिक स्थिति के नुकसान के डर के लिए कमीशन एजेंटों या बैंकों का दबाव 21.6 प्रतिशत आत्महत्याओं का नेतृत्व करता है। ऋणों पर लगाए गए उच्च ब्याज दरों और गैर-उत्पादक प्रयोजनों या फसलों की विफलता के लिए ऋण के मोड़ पर उन्हें कर्ज जाल में डाल दिया गया, जिससे आत्महत्याओं के लिए दबाव बना दिया गया।

नागेश (2005)ने बताया कि कर्नाटक में किसानों की आत्महत्याओं के लिए ऋणी मुख्य कारक थी। 48.6 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 61.6 प्रतिशत किसान परिवारों के ऋणी थे। अध्ययन में पाया गया कि बैंक ऋण (50 प्रतिशत) का प्रमुख स्रोत हैं, इसके बाद सावधानियों (20 प्रतिशत), सहकारी समितियों (16.9 प्रतिशत), रिश्तेदारों और मित्रों (6.8 प्रतिशत), और व्यापारियों और सरकारी एजेंसियों (प्रत्येक में 1.9 प्रतिशत)। हालांकि, अध्ययन से पता चला है कि कर्जदार किसानों के 34% कर्जदारों से उधार ली गई 32% ने बैंकों से 23% और सहकारी समितियों से 23% ऋण लिया। सत्तर एक प्रतिशत किसान न्यूनतम सहायता मूल्य योजना और 57 प्रतिशत किसानों के बारे में अनजान थे "फसल बीमा योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

रीजा पी. (2010)ने 100 आत्महत्या के प्रयासों और उन लोगों के परिवारों का चयन किया है जिन्होंने आत्महत्या की है। इस अध्ययन में शोधकर्ता ने पाया कि लगभग 28 लोग

आत्महत्या के बढ़ते दर से केरल में हर रोज आत्महत्या करते हैं। राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह लगभग तीन गुना अधिक है उनके अध्ययन में पाया गया कि अधिक पुरुष मादा की तुलना में आत्महत्या करते हैं और 80 प्रतिशत से अधिक आत्महत्या पीड़ित लोग 15-59 वर्षों के उत्पादक आयु वर्ग के थे। इसके अलावा, वहाँ आर्थिक समस्याओं और आत्महत्या के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से एक एसोसिएशन के बीच समान पाया जाता है। आर्थिक कारक में घरों के निर्माण और रखरखाव, घरेलू उपकरणों की खरीद, बेटियों के विवाह, शिक्षा व्यय के लिए बैंक ऋण शामिल हैं। इस अध्ययन में यह भी पता चलता है कि उच्च आय समूह की तुलना में कम आय वर्ग में आत्महत्या की दर अधिक है। वर्तमान अध्ययन में कहा गया है कि महिलाओं को पूर्ण आत्महत्या की स्वीकार्यता के प्रति मजबूत नकारात्मक दृष्टिकोण है लेकिन आत्महत्या के प्रयासों के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण। शहरी क्षेत्रों की तुलना में आत्महत्या ग्रामीण इलाकों में अधिक होती है।

गुरमीत कौर (2011)ने पंजाब राज्य के 455 किसानों के आत्महत्या के शिकार लोगों के अध्ययन के जरिए पंजाब राज्य में किसानों की आत्महत्या के मूल कारणों का पता लगाने की कोशिश की। संगरूर, मानसा, भटिंडा और फरीदकोट पंजाब के सबसे आत्मघाती प्रवण जिले हैं, जो कपास की बेल्ट है। उसने यह बताया है कि फसल की गहन खेती, फसल की गहन खेती, अनौपचारिक धन उधारदाताओं और बैंकों से ऋण उधार लिया गया है, परंपरागत फसलों की न्यूनतम समर्थन कीमतों में वृद्धि या धीरे-धीरे वृद्धि, ऋण के अनुत्पादक उपयोग में गिरावट के प्रमुख जिम्मेदार कारक हैं। किसानों की शुद्ध आय इसके अलावा, प्रतिकूल मौसम किसानों के जोखिम को बढ़ाता है पंजाब में किसानों के समुदाय के बीच कर्ज के दायरे बढ़ाने के लिए ये सभी कारक जिम्मेदार हैं। इसके विपरीत, परिवार के खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं और पंजाब में कृषि समुदाय में सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के प्रति किसानों का नेतृत्व किया जा रहा है। ये सभी समस्याएं किसानों के बीच अवसाद, चिंता, निराशा को बढ़ाती हैं इसलिए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

परिणाम एवं विवेचना- किसानों की आत्महत्या के कारण विदर्भ में दिनों दिन विधवाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। पूर्व केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने इस बात का दावा किया था कि वर्ष 2010 में 365 किसानों ने आत्महत्या की थी। यानी एक दिन में एक, इनमें से मात्र 65 ने कर्ज के कारण आत्महत्या की थी। लेकिन राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो इस दावे की पूरी तरह से पोल खोल देता है। अब सवाल यह है कि जब सरकार लागत के

अनुसार कपास की कीमत नहीं देती है तो फिर उसके निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाती है? इस बात को समझने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले साल 2009 में यह घटना घटी। 120 घंटे तक सरकार ने कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए रखा। लेकिन न जाने क्या बात है कि हड़बड़ी में लगाए गए इस प्रतिबंध को सरकार ने कुछ शर्तों के साथ रद्द कर दिया। पूर्व केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार का तो कहना था कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आनंद शर्मा ने इसका लूला-लंगड़ा बचाव किया। किन मिल मालिकों एवं धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने यह निर्णय लिया ये तो वे ही जानें। लेकिन जो समाचार मिल रहे हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने कुछ शक्तिशाली लोगों के लिए यह निर्णय लिया। उसके समाचार सारे देश में पहुंचे और सरकार आलोचना का शिकार बने इससे पहले ही अपने पाप को छिपाने का भरपूर प्रयास किया। निर्यात पर प्रतिबंध लगते ही भाव घटे जिसमें दलालों और पूंजीपतियों की चांदी हो गई। पिछले वर्ष भी ऐसा ही नाटक खेला गया था, जिसमें गुजरात के ही किसानों को 14 हजार करोड़ का नुकसान हुआ था।

किसान आत्महत्या से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्य 1995-2011

वर्ष	महाराष्ट्र	आंध्र-प्रदेश	कर्नाटक	मध्य-प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	इन राज्यों में कुल आत्महत्या	भारत में प्रतिवर्ष किसानों की आत्महत्या	पांचो राज्यों में कुल आत्महत्या का प्रतिशत
1995	1981	1196	2490	1239	6008	10720	56.04
1996	1917	1706	2011	1809	7507	13729	54.68
1997	2409	1097	1832	2390	7236	13622	53.12
1998	2423	1813	1883	2278	8383	16015	52.34
1999	3022	1974	2379	2654	9430	16082	58.64
2000	3536	1525	2630	2660	9837	166603	59.25
2001	3695	1509	2505	2824	10374	16415	63.20
2002	20066	1896	2340	2578	10509	17971	58.48
कुल (total)	20066	12716	18070	18432	69284	121157	57.19
2003	3836	1800	2678	2511	10825	17164	63.07

2004	4147	2666	1963	3033	11809	18241	64.74
2005	3926	2490	1883	2660	10959	17131	63.97
2006	4453	2607	1720	2858	11638	17060	68.22
2007	4238	1797	2135	2856	11026	16632	66.29
2008	3802	2105	1737	3152	10795	16196	66.66
2009	2872	2414	2282	3197	10765	17368	61.98
2010	3141	2525	2585	2363	10614	15964	66.49
2011	3337	20610	19083	23956	97401	149783	65.03
कुल	33752	20610	19083	23956	97401	149783	65.03
कुल 1995-2011	53818	33326	37153	42388	166685	270940	61.52

स्रोत - राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) रिपोर्ट 1995-2011

महाराष्ट्र में 1995 के बाद आत्महत्या करने वाले किसानों की कुल संख्या 54,000 का आंकड़ा छूने को है। इनमें से 33,752 किसानों ने 2003 के बाद आत्महत्या की है यानी इन नौ सालों में हर साल 3,750 किसानों ने आत्महत्या की। साथ ही महाराष्ट्र में 1995-2002 के बीच 20,066 किसानों ने आत्महत्या की थी यानी इन आठ सालों के दौरान हर साल 2,508 किसानों ने आत्महत्या की। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि किसानों की आत्महत्या में भी वृद्धि हो रही है और देश भर में उनकी संख्या भी घट रही है। महाराष्ट्र में यह समस्या शहरीकरण के कारण और भी भयावह हो जाती है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र देश का वह राज्य है जहां सबसे तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। 'बढ़ती आत्महत्या सिकुड़ती जनसंख्या' का समीकरण यह बताता है कि कृषक समुदाय पर दबाव बहुत बढ़ गया है।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विदर्भ क्षेत्र के बदहाल किसानों को राहत देते हुए 37 अरब 50 करोड़ रूपए के पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के तहत घोषित राशि में से 21 अरब 77 करोड़ रूपए की राशि कृषि परियोजनाओं पर ख़र्च की और किसानों का 7 अरब 12 करोड़ रूपए का कर्ज़ माफ़ कर दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रभावित परिवारों को तत्काल मदद देने के लिए विदर्भ क्षेत्र के सभी छह ज़िलाधिकारियों को 50-50 लाख रूपए दिए गए थे। इस राहत पैकेज को विदर्भ क्षेत्र के छह ज़िलों अमरावती, वर्धा, अकोला, वाशिम, बुलधाना और यावतमाल में इस्तेमाल किया जाना था। पूर्व प्रधानमंत्री ने पैकेज की घोषणा करते हुए पत्रकारों से कहा था , "विदर्भ के किसानों की समस्या हमारे लिए काफ़ी गंभीर विषय है। इसीलिए इस योजना के लागू होने की निगरानी मेरा कार्यालय ख़ुद करेगा। हम इस बात का

ध्यान रखेंगे कि जो वादे किए गए हैं, उन्हें पूरा किया जाए." उन्होंने कहा था कि इस पैकेज से क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति में तो सुधार होगा ही, साथ ही कर्ज़ का बोझ भी हल्का होगा किन्तु विदर्भ में आत्महत्या के आकड़ें सरकारी योजनाओं और उनके क्रियानव्यन की पोल खोल के रख दे रहे हैं।

वर्तमान महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़ण्वीस सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। 1 लाख 98 हजार करोड़ का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुधीर मुगंतिवार का फोकस कृषि, सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों के विस्तार पर रहा। सिंचाई व पीने के पानी की कमी ना हो इसीलिए प्रबंधन प्रणाली का विकेन्द्रीकरण करने हेतु 1000 करोड़ रुपए का कोष सरकार ने बनाया है। सूखाग्रस्त किसानों के लिए 4000 करोड़ रुपए का राहत कोष भी सरकार ने अलग से खर्च करने की सोची है। पूरे राज्य में सिंचाई के विकास और कड़े नियम के तहत प्रबंधन के लिए 7272 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विदर्भ में पूर्व मालगुजारी टंकियों के पुनःनिर्माण के लिए 100 करोड़, नाला बांध के काम के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है। नए युग की खेती यानि सूक्ष्म सिंचाई के लिए भी 330 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मनरेगा योजना के अंतर्गत 1948 करोड़, राष्ट्रिय कृषि योजना में 336 करोड़, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा योजना और कृषि नवीनीकरण के अंतर्गत 257 करोड़ तथा राज्य रोजगार गैरंटी योजना के लिए 700 करोड़ रुपयों का कोष रखा गया है। ग्रामीण मार्ग योजना की घोषणा की गयी जिसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण व विस्तार के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है और हर साल 1000 करोड़ रुपए तक इसे बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 790 करोड़ रुपए और जो इस योजना में ना गिने जाए उन सड़कों के कार्य के लिए 71 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 5000 किलोमीटर के सड़कों के मरम्मत और रखरखाव के लिए भी 3213 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मोदी सरकार की तर्ज पर 'आमदार आदर्श गाँव योजना' को लागू किया जाएगा जिसमें सभी विधायकों के लिए एक एक गाँव को गोद लेने की अनिवार्यता होगी। ग्रामीण कारीगरी व हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए वर्धा के सेवाग्राम में केंद्र की स्थापना की जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे आने वालों के लिए गृह निर्माण, पंडित दीनदायल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय योजना के अंतर्गत भूमि खरीदने हेतु 50,000 रुपए तक की सहायता गरीब परिवारों मो मिलेगी और 884 करोड़ रुपए की लागत से इन परिवारों के लिए 1 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। यह बजट और योजनाएं विदर्भ में कितनी सफल होगी यह समय ही बताएगा, लेकिन इस बजट से यह आशा जरुर लगाई जा सकती है कि विदर्भ जो भारत में किसान आत्महत्या के

स्थान के नाम से जाना जाता है, किसानों के लिए यह बजट शायद संजीवनी का कार्य करे।

उपसंहार:-विकास की राह पर आगे बढने के लिए गांववासियों और किसानों का निरंतर कम होना व शहरों व शहरवासियों का का निरंतर बढ़ना अनिवार्य है। कुछ देशों का यह अनुभव रहा है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि विकास कि राह पर आगे बढ़ने के साथ गांवों और खेती-किसानी की आजीविका को और मजबूत किया जाय, जहां एक ओर किसानों व विशेषकर छोटे किसानों की आजीविका को टिकाऊपन और मजबूती देना चाहिए, वहीं गांव व कस्बे के स्तर पर अधिक कुटीर व लघु उद्योगों को पनपाकर विविध तरह के रोजगारों व स्व रोजगारों का विस्तार होना चाहिए, जिससे ग्रामीण परिवारों को खेती के साथ-साथ, गांव में रहते हुए ही, अनेक अन्य रोजगार भी उपलब्ध हो सके। जलवायु बदलाव से जुड़े प्रतिकूल मौसम के इस दौर में खेती-किसानी को टिकाऊ और मजबूत बनाने के लिए सरकार के बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि बहुत जरूरी है। इस बढ़े हुए बजट का लाभ सीधे-सीधे छोटे व मध्यम किसानों को पर्यावरण की रक्षा से मेल रखने वाली खेती की प्रगति के लिए मिलनी चाहिए, खेती किसानी की समृद्धि व रक्षा के लिए केवल खेती किसानी की नीतियों व वजट में सुधार पर्याप्त नहीं है, इसके साथ पूरी अर्थव्यवस्था में ऐसे बदलाव जरूरी हैं जो गांव-पक्षीय व किसान-पक्षीय हों। उदाहरण के लिए औद्योगिक नीति में ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे गांवों, कस्बों व छोटे शहरों में कुटीर व छोटे उद्योग अधिक पनप सके।

समस्त विवेचन से यह तो निसंदेह कहा जा सकता है, की भारतीय किसान अपना जीवन कष्टमय रूप में निर्वाह कर रहा है। कृषि की दयनीय हालत के बावजूद अपने पहले बजट में सरकार ने कृषि आय की बात तो की, लेकिन कृषि बजट में कटौती कर दी। बजट में किसानों के लिए बजट में कुछ खास नहीं रहा। सरकार द्वारा जिस कृषि लोन की बात की जाती है। उसका फायदा किसानों से ज्यादा कृषि उद्योग से जुड़े लोगों को होता है। सरकार की अब तक की नीतियों और केंद्रीय बजट का साफ संदेश है कि किसानों को वह सांत्वना मात्र देने को तैयार नहीं हैं। किसानों की आत्महत्या इस विषय पर जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना और जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना होगा। किसानों की आत्महत्या दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करने का उद्देश्य सामने रखकर समाचारों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार और भविष्य की आने वाली सरकारों से भारतीय किसान यही उम्मीद लगायें हुए बैठा है कि कब उसके दिन बदलेंगे। अब तो यह वर्तमान सरकार और भविष्य की आने वाली सरकारों पर निर्भर करता है कि देश की भूख मिटाने वाले अन्नदाता की भूख कब मिटेगी यह भविष्य की गर्त में है। समस्त आंकड़ों के

विवेचन और सरकारी योजनाओं के अवलोकन से फ़िलहाल यह आशा की जा सकती है की किसनों की आत्महत्या और उनकी समस्याओं का समाधान जरुर होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. रेड्डी, नरसिम्हा और श्रीजीत मिश्रा (2009)। भारत में कृषि संकट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

2. मिश्रा श्रीजीत और अन्य (2006), "महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या: एक पृष्ठभूमि पेपर", इंदिरा गांधी विकास संस्थान, मुंबई (एमएच), जनवरी 2006।

3. फर्नांडो, निक्सन, अरुण कुमार, और एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट (पुणे, भारत)। विदर्भ में किसानों की आत्महत्याओं की त्रासदी: एक सबक और उम्मीद की किरण नई दिल्ली: रूपा एंड कं।

4. आर.एस. देशपांडे (2010) - "किसानों की परेशानी और अप्रियता: मिस्र एंड मिथ्स।" कृषि विकास और ग्रामीण परिवर्तन केंद्र, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलोर। आरएसडी / सिम्बायोसिस / ड्राफ्ट पेपर / 11-01-08

5. डा. ज्ञानमुद्र (2007) - किसान आत्महत्या: गतिशीलता और रोकथाम की रणनीति- पीपी- 3.10 संपादित पुस्तक दीप और दीप पब नई दिल्ली, 2007

6. देशपांडे आर एस (2002), "कर्नाटक में किसानों द्वारा आत्महत्या: कृषि संकट और संभावित सुलह कदम", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 37 (26), 2 9 जून, 2002, पीपी 2601-2610।

7. विद्यासागर, आर, और सुमन चंद्र, के।, 2004. किसान " आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आत्महत्याएं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद, पी .133

8. जयंती घोष (2005) - "आंध्र प्रदेश सरकार के किसानों के कल्याण पर आयोग की रिपोर्ट। www.macroscan.net/pol/apros/pdf।

9. सुचा, एस. गिल, 2005. ग्रामीण पंजाब में आर्थिक दुःख और किसान आत्महत्या, पंजाब अध्ययन की जर्नल, खंड 12, नंबर 2

10. रीजा पी. (2010), "आत्महत्या के कारण और परिणाम: केरल के एक केस अध्ययन", पीएचडी थीसिस, केरल विश्वविद्यालय,

11. गुरमीत कौर (2011), "ग्रामीण पंजाब में किसानों की आत्महत्याओं का एक विश्लेषण", पीएचडी थीसिस, पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला

12. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) रिपोर्ट 1995-2011

13. कुरुक्षेत्र अंक-हरितक्रांति जून, 2008.

14. दीनानाथ, मनोहर. (2008). खेती का नया तंत्र और किसानों की आत्महत्या. श्रवण प्रकाशन: बारामती.

15. तिवारी, अर्जुन. (2004). जनसंचार एवं हिंदी पत्रकारिता. जय भारती प्रकाशन: इलाहबाद.

16. दैनिक भास्कर. 2 फरवरी 2015, नागपुर.

17. लोकमत. 4 मार्च 2015, नागपुर.

18. कुमार, मनोज. (मार्च 2011). समागम शोध पत्रिका, भोपाल.